भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4245

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण

4245. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड) क्या गुणवत्ता में कमी के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खरीद से लेकर वितरण तक खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार करके जारी किया है।

(ग) और (घ): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों की मशीनरी द्वारा खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और आकस्मिक नमूनाकरण किया जा रहा है। ऐसे मामलों में, जहां खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं तो एफएसएस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ड.) और (च): टीपीडीएस के तहत, प्रत्येक राज्य सरकार को एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति या निर्धारित अन्य तंत्र शामिल हो सकते हैं। जब भी इस विभाग को किसी भी स्रोत से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है

*****